

अनुदान संख्या 96 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

GRANT No. 96 - MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5409,92,00		
			5409,93,00	2450,13,05
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2959,75,40
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	33,48,00	19,35,27	-14,12,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			14,12,74

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई थी:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	1819.00		
		
पु.	R.	-1819.00		..

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष “2553”	Major Head “2553”			
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	MPs Local Area Development Scheme			
मू.	O.	395850.00		
			120057.33	120057.33
पु.	R.	-275792.67		..
मुख्य शीर्ष “3454”	Major Head “3454”			
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census, Surveys and Statistics			
मू.	O.	139579.00		
पू.	S.	1.00	121464.76	121460.62
पु.	R.	-18115.24		-4.14

(I) मुख्य शीर्ष “2552” – “सर्वेक्षण और सांख्यिकी आर्थिक सलाह और सांख्यिकी – सांख्यिकी – क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास – पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस नमूना कार्य करने के लिए राज्यों को अनुदान सहायता)” के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में ₹1819.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1819.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head “2552” - “Surveys and Statistics Economic Advice and Statistics - Statistics - Capacity Development (Capacity Development of NSSO- Grant-in-aid to the States for carrying out Central NSS sample work in North Eastern Region)” - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष “2553” – “जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सहायता – अनुदान सहायता” के अंतर्गत ₹275792.67 लाख की बचत (₹395850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता जिला प्राधिकरणों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एम पी एल ए डी योजना के तहत

(II) Under Major Head “2553” - “Assistance to District Rural Development Agencies - Grant Assistance” - saving of ₹275792.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹395850.00 lakhs) was due to less utilisation of funds by the implementing District

निधियों के कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3454” – “सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचत हुई:—

(का) “राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन – अधीनस्थ कार्यालय” – ₹2735.50 लाख की बचत (₹45245.92 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और कम छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(खा) “भारतीय सांख्यिकी संस्थान – आई.एस.आई, कोलकाता को अनुदान सहायता” – ₹523.43 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹31546.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ निर्माण प्रस्तावों का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(गा) “केंद्रीय सांख्यिकी संगठन – क्षमता विकास (सी एस ओ का क्षमता विकास और संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण)” – ₹13842.77 लाख की बचत (₹54956.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जाने और मुकदमे के कारण राष्ट्रीय एकीकृत सूचना परियोजना (एनआईआईपी) के पूरा न होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹426.34 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत है।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित की गई राशि (₹1412.74 लाख) ₹1412.73 लाख की कुल बचत से अधिक थी।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:—

Authorities/implementing agencies towards MPLAD Scheme.

(III) Under Major head “3454” - “Survey and Statistics” - savings occurred under the following heads:-

(A) “National Sample Survey Organisation - Subordinate Office” - saving of ₹2735.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45245.92 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less leave travel concession claims.

(B) “Indian Statistical Institute - Grant-in-aid to ISI, Kolkata” - saving of ₹523.43 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹31546.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) was due to non-materialization of some construction proposals.

(C) “Central Statistical Organisation - Capacity Development (Capacity Development of CSO and Institutional Development & Capacity Building)” - saving of ₹13842.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54956.00 lakhs) was due to hiring of less outsourced staff and non-completion of National Integrated Information Project (NIIP) owing to litigation.

(IV) Under one head saving of ₹426.34 lakhs occurred constituting 62 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹1412.74 lakhs) exceeded the overall savings of ₹1412.73 lakhs.

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual	अधिक व्यय+ Excess+
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"			
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services			
मू.	O.	3348.00		
			1935.26	1935.27
				+0.01
पु.	R.	-1412.74		

(I) "सांख्यिकी - क्षमता विकास (सीएसओ का पूंजीगत विकास और संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण)" के अंतर्गत - ₹1343.88 लाख की बचत (₹3225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईटी उपकरणों, भूमि, मशीनरी, मोटर वाहनों और फर्नीचर एवं फिक्सचर के लिए खरीद प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिये जाने के कारण हुई।

(I) Under "Statistics - Capacity Development (Capital Development of CSO and Institutional Development & Capacity Building)" - saving of ₹1343.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3225.00 lakhs) was due to non-materialisation of procurement proposals for IT equipments, land, machinery, motor vehicles and furniture & fixtures.